राजनीति का अपराधीकरण

प्रीलिम्स के लिये:

एमिकस क्यूरी, जनप्रतिनिधित्व कानून, राजनीति का अपराधीकरण।

मेन्स के लिये:

राजनीति के अपराधीकरण का कारण, प्रभाव और समाधान।

चर्चा में क्यों?

न्याय मित्र (Amicus Curiae) द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, **1 दिसंबर, 2021** तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े **कुल 4,984 आपराधिक मामले** लंबित थे।

- **न्याय मित्र (Amicus Curiae)** को सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालतें स्थापित करने में मदद के लिये नियुक्त किया था।
- यह प्रवृत्ति राजनीति के अपराधीकरण की बढ़ती घटनाओं को उजागर करती है।
- **न्याय मित्र (शाब्दिक रूप से "अदालत का मित्र")** वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है तथा जो मामले में मुद्दों पर असर डालने वाली जानकारी, विशेषज्ञता या अंतर्दृष्टि प्रदान करके अदालत की सहायता करता है।

राजनीति का अपराधीकरण:

- इसका अर्थ राजनीति में **अपराधियों की बढ़ती भागीदारी** से है, जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं।
- **यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच साँठगाँठ के कारण होता है।**

आपराधिक छवि के उम्मीदवारों की अयोग्यता का कानूनी पहलू:

- भारतीय संविधान में संसद या विधानसभाओं के लिये चुनाव लड़ने वाले किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में उपबंध नहीं किया गया है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विधायिका का चुनाव लड़ने के लिये किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है।
  - इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है और दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है।
  - इस अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य (सांसद अथवा विधायक) हत्या, बलात्कार, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जैसे अपराधों में लिप्त है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

अपराधीकरण का कारण:

- **कार्यान्वयन का अभाव: राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिये बने कानूनों और निर्णयों के कार्यान्वयन की कमी के कारण इसमें बहुत मदद नहीं मिली है।**
- **संकीर्ण स्वार्थ:** राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जाति या धर्म जैसे सामुदायिक हितों से प्रभावित होकर मतदान करता है।
- **बाहुबल और धन का उपयोग:** गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिये वे दल के चुनावी अभियान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है।

- इसके अतरिकि्त कभी-कभी तो मतदाताओं के पास कोई वकिल्प नहीं होता है, क्योंकि सभी प्रतयोगी उम्मीदवार आपराधकि प्रवृत्ति के होते हैं।

//

प्रभाव:

- **स्वतंत्र और नष्पिक्ष चुनाव के सद्धिांत के वरिुद्ध:**
  - यह एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करने के लयि मतदाताओं की पसंद को सीमति करता है।
  - यह स्वतंत्र और नष्पिक्ष चुनाव के लोकाचार के खलिाफ है जो कि लोकतंत्र का आधार है।
- **सुशासन पर प्रभाव:**
  - प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाते हैं, इससे सुशासन स्थापति करने में लोकतांत्रकि प्रक्रयिा की प्रभावकारति प्रभावति होती है।
  - भारतीय लोकतांत्रकि प्रणाली में यह प्रवृत्ति यहाँ के संस्थानों की प्रकृति तथा वधियिका के चुने हुए प्रतनिधियिों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती है।
- **लोक सेवकों के कार्य पर प्रभाव:**
  - इससे चुनावों के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन बढ़ जाता है, जसिसे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा लोक सेवकों के काम पर असर पड़ता है।
- **सामाजकि भेदभाव को बढ़ावा:**
  - यह समाज में हसिा की संस्कृति को प्रोत्साहति करता है और भावी जनप्रतनिधियिों के लयि एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

आगे की राह

- चुनाव सुधार पर बनी वभिन्नि समतियिों (दनिेश गोस्वामी, इंद्रजीत समति) ने राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन कयि जाने की सफिारशि की, जसिसे काफी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मलिेगी और परणािमस्वरूप राजनीति के अपराधीकरण को सीमति कयिा जा सकेगा।
- एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रयिा हेतु राजनीतकि पार्टयिों के मामलों को वनियिमति करना आवश्यक है, जसिके लयि नरि्वाचन आयोग (Election

Commission) को मज़बूत करना ज़रूरी है।

- मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य प्रलोभनों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- भारत के राजनीतिक दलों की राजनीति के अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानिकारक प्रभावों को रोकने के प्रति अनिच्छा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले पर विचार करना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/criminalization-of-politics-2